abolished with effect from 1st January, 1966. The State Government took this decision, it is understood, mainly on the ground that since bulk of the work in the blocks concerns the agriculture sector. the Department of Agriculture could attend to it directly through its own hierarchy.

Government of India have so far received no specific proposals from any other State Government for the abolition of the posts of Block Development Officers.

Use of Helicopters during Elections

853. **Shri George Fernandes:**
Shri Madhu Limaye:
Shri J. H. Patel:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints regarding the use of a helicopter in contravention of the rules and safety regulations in the election campaign in February, 1967 in Bombay city;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the action taken thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Food aid from U.S.A.

855. **Shri D. C. Sharma:**
Shri Ram Singh:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Yajnik:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) whether the allegations that Government have accepted very humiliating terms to secure food under PL 480 agreement and other aids from the United States have been looked into;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps proposed to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Government of India have not accepted any humiliating terms to secure food under PL 480 agreement and other aid from the United States.

(b) and (c). Do not arise.

बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास में नलकूप लगाना

856. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958 से पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास में क्रमश: कितने नलकूप लगाये गये थे तथा उसके बाद 1966 तक इन राज्यों में कितने नलकूप लगाये थे ;

(ख) प्रत्येक राज्य में क्रमश: कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है;

(ग) मरम्मत न होने के कारण प्रत्येक राज्य में कितने नलकूप प्रयोग में नहीं आ रहे हैं ; और

(घ) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इन राज्यों में नये नलकूप लगाने तथा पुराने नलकूपों की मरम्मत करने पर क्रमश: कितनी रकम खर्च की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ). बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास सरकारों से अपेक्षित जानकारी मांगी जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्यान्नों के मूल्य

857. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री मोहसिन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उनका प्रत्येक राज्य में पृथक्-पृथक् रूप से मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) किसी भी राज्य में बाजार भावों पर सरकारी उपायों के प्रभाव को अलग करके बताना कठिन है ।

विवरण

देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन बढ़ा कर केवल दीर्घकाल में खाद्यान्नों के भावों में गिरावट लायी जा सकती है । इसके लिए सरकार ने विभिन्न उपाय अपनाये हैं। खाद्यान्नों की कमी से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए, जिसके फलस्वरूप भाव भी बढ़ गये हैं, सरकार ने धीरे धीरे सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया है। अब इस प्रणाली के अन्तर्गत 23 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या आ चुकी है और केन्द्रीय सरकार सहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण करने के लिए काफी मात्रा में खाद्यान्न देती है । खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट लाने के लिए उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण उपायों में ये उपाय शामिल हैं—अधिप्राप्ति तेज करना, बहुत अधिक आयात करना, व्यापार पर नियामक उपाय, बैंक आदि की पेशगियों पर नियन्त्रण ।

संसद तथा विधान सभाओं के लिये चुनाव

858. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् तथा विधान सभाओं के लिये अलग-अलग समय पर चुनाव कराने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुये हैं :

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है; और

(ग) इस बारे में चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) इस सुझाव के समर्थन में दिया गया कारण यह था कि इससे देश में स्वस्थ लोक तंत्र और द्वि-दलीय पद्धति का जन्म होगा और वे रहेंगे ।

(ग) निर्वाचन आयोग इस सुझाव से उन कारणों से सहमत नहीं हुआ जो भारत में तृतीय साधारण निर्वाचन, 1962 पर रिपोर्ट के अध्याय 7 के पृष्ठ 44 पर कथित है और इस प्रकार हैं :

केरल और उड़ीसा की विधान सभायें क्रमशः फरवरी 1960 और जून 1961 में ही निर्वाचित हुई थीं और इसके परिणाम-स्वरूप 1962 में, इन दो राज्यों में, जहां तक उनकी विधान सभाओं का सम्बन्ध है, साधारण निर्वाचन नहीं होने थे । इस बात से कि दो राज्य इस प्रकार अलग पड़ गये हैं और भविष्य में उन्हें अपने विधान सभा निर्वाचन, देश में संसदीय साधारण निर्वाचन, से एक या दो वर्ष पूर्व कराने पड़ेंगे, यह दिलचस्प प्रश्न पैदा होता है कि क्या यह वांछनीय परिस्थिति नहीं है । यह कहा जा सकता है कि दोनों साधारण निर्वाचनों का पृथक्करण करने और हरएक राज्य में उनको अलग-अलग कराने से निर्वाचकों को,